>

Title : Need to increase funds provided under Members of Parliament Local Area Development Scheme.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सरकार ने यह माना है कि एमपीलैड्स के तहत जो काम हुए हैं वो विकास की राह में मील का पत्थर है, वो ऱÂट्र की सम्पति है। दूसरी तरफ सरकार ने इसे दो करोड़ रूपये तक सीमित कर दिया है। निर्माण सामग्री का दाम और मजदूरी बढ़ जाने से सभी काम करवाना, आजकल ज्यादा बजट का हो गया है जो कि 2 करोड़ रूपये में संभव नहीं है। दूसरी तरफ सरकार मानती हे कि परिसीमन के बाद संसदीय क्षेत्र का भौगोलिक स्वरूप बदल गया है।

सरकार यह भी मानती है कि मौद्रिक अवमूल्यन के बाद वास्तविक राशि का मूल्य केवल एक करोड़ छह हजार रूपये रह गया है जो कि बहुत ही कम है।

कई संसदीय क्षेत्रों का भौगोलिक स्वरूप बदल गया है और काफी बड़ा भी हो गया है।

चौदहवीं लोक सभा में मेरा संसदीय क्षेत्र नालन्दा जिसको मैं 15वीं लोक सभा में प्रतिनिधित्व करता हूँ, में केवल 6 विधान सभा क्षेत्र थे और अभी पूरा का पूरा नालन्दा जिला इसमें आ गया है जहां कि आठ विधान सभा क्षेत्र थे जिसकी आबादी लगभग 30 लाख है और यह देश के सबसे बड़े संसदीय क्षेत्रों में एक है। यहां पर 20 ब्लॉक हैं। जनप्रतिनिधि के उपर काफी दबाव भी रहता है। ऐसे में 2 करोड़ रूपये से काम नहीं चलेगा।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि आबादी के हिसाब से एवं बड़े संसदीय क्षेत्र के हिसाब से इसको बढ़ाया जाना चाहिए।